ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश : निर्मला

वित्तमंत्री सीतारमण बोलीं—राजकोषीय अनुशासन का असर दिखा

नई दिल्ली, 07 निर्मला सीतारमण ने भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति और उच्च विदेशी मुद्रा भंडार ने भारतीय रिजर्व बैंक को नीतिगत फैसलों में अधिक लचीलापन प्रदान किया है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले एक दशक में अपनाए गए राजकोषीय अनुशासन के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अब पूंजीगत व्यय को बनाए रखने, जरूरतमंद क्षेत्रों को लक्षित सहायता देने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने की स्थिति में है. साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि मजबूत आर्थिक आधार के चलते आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती जैसे कदम उठाने की भी गुंजाइश बन सकती है.यह बयान ऐसे समय में आया है जब आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करने वाला है. वैश्विक अनिश्चितताओं, बढ़ती महंगाई और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच यह बयान आर्थिक दिशा को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसके साथ ही, देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना मजबूत है कि वह लगभग 11 महीनों के आयात को कवर कर सकता है, जो किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से निपटने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है. हालांकि, वित्त मंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों को लेकर चिंता भी जताई. उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को एक 'प्रणालीगत झटका' बताते हुए कहा कि इससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है. कच्चे तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि और मुद्रा पर दबाव से महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है.

> सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे निर्णयों से उपभोक्ताओं को राहत दी गई है. साथ ही, सरकार ने अपने उधारी कार्यक्रम को घटाकर 17.2 लाख करोड़ रुपये से 16.09 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ेगी और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. इस प्रकार, मजबूत आर्थिक आधार और संतुलित नीतियों के जरिए भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच भी स्थिरता बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

अमूल-सारस्वत बैंक ने छुआ 1 लाख करोड़ कारोबार

नई दिल्ली, 7 अप्रैल. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दो प्रमुख सहकारी संस्थाओं सारस्वत सहकारी बैंक और अमूल तथा उनमें कार्यकर रहे लोगों को वर्ष 2025-26 में वार्षिक एक लाख करोड़ रुपये के कारोबार का आंकड़ा पार करने के लिए बधाई दी है. श्री शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कहा कि सारस्वत सहकारी बैंक और अमूल द्वारा वर्ष 2025-26 में एक लाख करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर का आंकड़ा पार करना, सहकारिता की शक्ति और उसकी अपार संभावनाओं का जीवंत उदाहरण है. यह उपलब्धि न केवल सहकारी बैंकिंग और डेयरी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि इससे आत्मनिर्भर भारत की निर्माण यात्रा को भी नई ऊर्जा मिलने वाली है.

गोल्ड-सिल्वर में गिरावट, निवेशकों को मौका

1,400 रुपए नीचे आया सोना

2600 रुपए सस्ती हुई चांदी

नई दिल्ली, 7 अप्रैल. भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और खरीदारों को राहत मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार, 24 कैरेट सोने के भाव में 1400 रुपये से अधिक की गिरावट आई है, जबकि चांदी भी 2600 रुपये से ज्यादा सस्ती हुई है.

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 999 शुद्धता वाला सोना घटकर 1,47,489 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. वहीं, चांदी की कीमत गिरकर 2,31,435 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और मांग में बदलाव के चलते कीमती धातुओं में यह गिरावट देखने को मिल रही है. सोने-चांदी की कीमतों में आई इस कमी को शादी-विवाह और निवेश के लिहाज से अच्छा अवसर माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब कीमतें हाल ही में ऊंचे स्तर पर थीं. सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, लगभग सभी शुद्धता के सोने के भाव में कमी दर्ज की गई है, जबकि चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट आई है.

> ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट (999 शुद्धता) सोना 1,410 रुपये सस्ता होकर 1,47,489 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह 23 कैरेट सोना 1,405 रुपये गिरकर 1,46,898 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. 22 कैरेट सोने में 1,291 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद इसका भाव 1,35,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इसके अलावा, 18 कैरेट सोना 1,057 रुपये सस्ता होकर 1,10,617 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 14 कैरेट सोना 825 रुपये गिरकर 86,281 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

देश का कपड़ा बाजार 15 साल में हुआ तीन गुना

नई दिल्ली, 07 अप्रैल. देश का कपड़ा बाजार पिछले 15 साल में तीन गुना होकर लगभग 15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.

कपड़ा मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी घरेलू वस्त्र मांग पर कपड़ा एवं वस्त्र बाजार पर राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, पिछले 15 साल में कपड़ों की घरेलू मांग में मजबूत वृद्धि हुई है और इसका बाजार 2010 के 4.89 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 14.95 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. इस प्रकार इसमें औसतन 8.3 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गयी है. मंत्रालय के अंतर्गत टेक्सटाइल्स कमेटी द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार, कुल बाजार आकार में घरेलू क्षेत्र का योगदान 2010 में 4.18 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2024 में 8.77 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसने देश में कपड़ों की मांग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि पिछले 15 साल में पुरुषों की जींस और महिलाओं के लेगिंग्स की मांग सबसे तेजी से बढ़ी है.

साथ ही एक गौर करने वाली बात यह है कि तकनीकी वस्त्रों की इस्तेमाल शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में अधिक होता है. केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज यह रिपोर्ट जारी की. इस अवसर पर वस्त्र सचिव नीलम शमी राव तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. रिपोर्ट के अनुसार, 15 साल में कपड़ों की प्रति व्यक्ति मांग 2,119 रुपये से बढ़कर 6,066 रुपये पर पहुंच गयी जो 7.8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है.कुल मांग में मानव निर्मित और मिश्रित रेशों पर आधारित उत्पादों का योगदान 52.2 प्रतिशत है, जबकि कपास आधारित उत्पादों का योगदान 41.2 प्रतिशत है. वहीं, रेशम और ऊनी उत्पाद क्रमशः 5.2 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत का योगदान देते हैं.

> कपास ने दूसरे सबसे महत्वपूर्ण रेशे के रूप में अपनी स्थिति बनाये रखी है. मूल्य के आधार पर इसकी मांग 0.87 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.53 लाख करोड़ रुपये हो गयी. इसकी वृद्धि दर दहाई अंक में 10.53 प्रतिशत रही. इसी अवधि में रेशम और ऊनी उत्पादों की मांग क्रमशः 8.93 प्रतिशत और 7.02 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी. अध्ययन में पता चला है कि महिलाओं ने कुल वस्त्र खरीद में 55.5 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि पुरुषों का योगदान 44.5 प्रतिशत रहा.

शेयर बाजारों में तेजी आई सेंसेक्स 510 अंक चढ़ा

मुंबई, 07 अप्रैल. घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार चौथे दिन तेजी देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स 509.73 अंक (0.69 प्रतिशत) चढ़कर 74,616.58 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 155.40 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की बढ़त में 23,123.65 अंक पर पहुंच गया. शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में तेजी लौट आयी. सुबह के कारोबार में सेंसेक्स एक समय 800 अंक से ज्यादा लुढ़क गया था, लेकिन दोपहर बाद कम कीमत पर हुई लिवाली से यह हरे निशान में लौट गया. मझौली कंपनियों में तेजी रही जबकि छोटी कंपनियों में बिकवाली हावी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.43 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. वहीं, स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.06 प्रतिशत फिसल गया. आईटी कंपनियों में दोपहर बाद लिवाली तेज होने से बाजार को समर्थन मिला. धातु, रियलटी, एफएमसीजी, निजी बैंकों और मीडिया कंपनियों के समूहों में भी तेजी रही. वहीं, सार्वजनिक बैंक और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूह गिरावट में रहे.

नैनो उर्वरक से कृषि में नई क्रांति : संधाणी

इफ्को का बड़ा कीर्तिमान, 4100 करोड़ का लाभ दर्ज

संस्था किसानों की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है.

नई दिल्ली, 07 अप्रैल. इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संधाणी ने कहा की, भारतीय सहकारिता आंदोलन के इतिहास में वित्तीय वर्ष 2025 -26 एक मिल का पत्थर बनाकर उभरा है. 1967 में मात्र 57 सहकारी समित्तियों के साथ शुरू हुई इफ्को की यात्रा आज 36,000 से अधिक समितियों और करोडो किसानो के विश्वास की पहचान बन चुकी है.

विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी सहकारी संस्था के रूप में स्थापित होना केवल एक उपलब्धी नहीं, बल्कि भारत की सहकारिता शक्ति का जीवंत प्रमाण है. इस स्वर्णिम वर्ष में इफ्को ने रु. 4,106 करोड़ से अधिक का सर्वकालिक रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया. यह उपलब्धी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि उन किसानो की मेहनत, कर्मचारीयों के समर्पण और सहकारिता के मूल्यों की विजय गाथा है.

उत्पादन और बिक्री के क्षेत्र में भी इफ्को ने नए कीर्तिमान स्थापित किए. 118.74 लाख मेट्रिक टन उर्वरक की रिकॉर्ड बिक्री और देशभर में 119.68 लाख मेट्रिक टन की आपूर्ति इस बात का प्रमाण है की संस्था किसानो की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. यूरिया और डी. ए. पी. की बढ़ती बिक्री ने कृषि क्षेत्र में इफ्को की निर्णायक भूमिका को और सुदृढ़ किया है.

मॉर्गन स्टेनली ने भारत की वृद्धि का अनुमान घटाया

नई दिल्ली, 7 अप्रैल. पश्चिम एशिया और पश्चिमी देशों की कठिन परिस्थितियों के मद्देनज वित्त और निवेश के कारोबार में लगे वैश्विक संगठन मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अनुमान को प्रतिशत 0.30 अंक घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है. इससे पहले संगठन ने 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया था. मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि 2026-27 में कच्चे तेल की औसत कीमत 95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहेगी तथा गैस की उपलब्धता एक अतिरिक्त बाधा होगी. मॉर्गन स्टेनली की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन की बढ़ती कीमत और औद्योगिक आपूर्ति में कमी से उत्पादन के संसाधनों की लागत बढ़ रही हैं.

एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली, 07 अप्रैल. टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. एयरलाइंस ने मंगलवार को बताया कि नये सीईओ की नियुक्ति तक वह पद पर बने रहेंगे.

> विल्सन ने कहा कि पिछले चार साल के उनके कार्यकाल में निजीकरण के बाद एयर इंडिया में चार एयरलाइंस का सफल अधिग्रहण और विलय हुआ. इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की कार्यप्रणाली की ओर बदलाव हुआ है. नेतृत्व टीम, कार्यबल, संस्कृति और काम करने के तरीकों में भी सुधार हुआ है. इसमें सिस्टम का पूर्ण आधुनिकीकरण, नये उत्पादों की शुरुआत, बेहतर सेवा मानकों का लागू होना, और बेड़े में 100 अतिरिक्त विमानों का शामिल होना भी शामिल है.

एयर इंडिया बोर्ड ने एक समिति का गठन किया है, जो आने वाले महीनों में उनके उत्तराधिकारी का चयन करेगी. एयर इंडिया की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री विल्सन ने साल 2024 में ही एयर इंडिया के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन को 2026 में पद छोड़ने की अपनी मंशा से अवगत करा दिया था और तब से वह यह सुनिश्चित करने में लगे थे कि संगठन और नेतृत्व टीम इस बदलाव के लिए तैयार हो. श्री चंद्रशेखरन ने पिछले चार साल में श्री विल्सन के नेतृत्व और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 के बाद आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं, नये विमानों की डिलीवरी में देरी, रेट्रोफिट कार्यक्रमों पर प्रभाव, भू-राजनीतिक और अन्य चुनौतियां में उन्होंने अपनी टीम के साथ दृढ़ता और संकल्प का परिचय दिया.

चावल मजबूत, चीनी नरम, दालों और खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 07 अप्रैल. घरेलू थोक जिंस बाजारों में सोमवार को जहां चावल की औसत कीमतें बढ़ी, वहीं गेहूं की कीमत लगभग स्थिर रही जबकि चीनी में नरमी की रुख रहा. दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव देखा गया. औसत दर्जे के चावल का औसत भाव 29 रुपये बढ़कर 3,856 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया. गेहूं 2,785 रुपये प्रति क्विंटल पर कमोबोश स्थिर रहा. आटे की कीमत सात रुपये प्रति क्विंटल घट गयी. दाल-दलहनों में उतार-चढ़ाव रहा.

निम्न मध्यम आय वर्ग के मकानों की मांग में तेज गिरावट

मुंबई, 07 अप्रैल। भारतीय आवासीय रियल एस्टेट बाजार में इस कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही के दौरान निम्न मध्य वर्ग श्रेणी के मकानों की मांग में तेज गिरावट के चलते बाजार की रफ्तार में सुस्ती देखी गयी है, हालांकि मांग के मूल कारक मजबूत बने हुए हैं।

भू-सम्पत्ति बाजार परामर्श कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट- इंडिया रियल एस्टेट - ऑफिस एंड रेजीडेंसियल (जनवरी-मार्च 2026) में पाया गया है कि इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में 50 लाख रुपये से कम के और 50 लाख से एक करोड़ रुपये के बीच के मकानों की बिक्री में 23 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की तेज गिरावट है तथा इस खंड में खरीदारों को समर्थन दिये जाने की जरूरत है। बिक्री में गिरावट के बावजूद सम्पत्तियों का भाव तेज है। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के बाजार में कीमतों में वृद्धि ज्यादा दिखी है। मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष की पहली तिमाही के दौरान मकानों की बिक्री और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़कर 10,028 यूनिट हो गया है।

समाचार विशेष

बिल्कुल अलग है बोडोलैंड की राजनीति

बीटीआर क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टियों और दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला

गुवाहाटी. ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित बोडोलैंड असम की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है. इसे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र या बीटीआर भी कहते हैं. यह असम राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है और इसमें असम के पांच जिले कोकराझार, चिरांग, उदालगुड़ी, बक्सा और तामुलपुर आते हैं.

इस क्षेत्र में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं और इस क्षेत्र के मुद्दे असम के अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग हैं. यह एक स्वायत्त क्षेत्र है, लंबे समय से हिंसा का शिकार रहा है और यहां एक अलग राज्य की मांग को लेकर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं. ऐसे में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की 15 सीटें निर्णायक साबित हो सकती हैं.

बोडोलैंड की राजनीति को समझने के लिए इस इलाके के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है. इसका इतिहास बोडो जनजाति की पहचान, अधिकार और स्वायत्तता की मांग से जुड़ा हुआ है. 1980 के दशक में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी, जो आगे चलकर कई बार हिंसक आंदोलनों में बदल गई. 1993 में पहला बोडो समझौता हुआ लेकिन इससे स्थायी समाधान नहीं निकला. इसके बाद 2003 में भारत सरकार, असम सरकार और उग्रवादी संगठन बोडो लिब्रेशन टाइगर्स के बीच समझौते से बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन हुआ, जिससे क्षेत्र को स्वायत्त शासन मिला. बाद में 2020 के नए समझौते के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र को और मजबूत किया गया, जिससे आज यह असम में एक सवायत्त क्षेत्र के रूप में है.

बीटीआर क्षेत्र में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों और दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबला है.

किस पार्टी को हो सकता है फायदा?

बोडो क्षेत्र में चुनाव असम के दूसरे हिस्सों से अलग होते हैं. इस क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव होता है. बीपीएफ और यूपीपीएल मुख्य पार्टियां हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में बीपीएफ हाग्रामा मोहिलारी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे. उस समय हिमंत बिश्वा शर्मा उन पर जमकर हमले करते थे लेकिन पांच साल में राजनीति पूरी तरह से बदल गई है. हाग्रामा मोहिलारी अब सीएम हिमंत के सहयोगी हैं और साथ में चुनाव लड़ रहे हैं. भले ही बीजेपी राज्य में बड़ी पार्टी हो लेकिन इस क्षेत्र में हाग्रामा मोहिलारी की बीपीएफ ही बड़े भाई की भूमिका में है.

पवार की राजनीति पर नजर

मुंबई. शरद पवार की सेहत ऐसी नहीं है कि वे पहले की तरह सक्रिय होकर महाराष्ट्र में राजनीति कर सकें. लेकिन फिर से राज्यसभा जाकर उन्होंने ऐसा संकेत दिया है कि वे एक पारी और खेलने के लिए तैयार हैं. हालांकि यह पारी कैसी होगी यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है.

वैसे भी शरद पवार की राजनीति समझना सबके वश की बात नहीं होती है. जाने माने पत्रकार वीर सांघवी ने अपनी किताब में उनके बारे में लिखा है कि अगर हवाईअड्डे पर पवार के हाथ में मुंबई जाने वाली उड़ान का बोर्डिंग पास दिखे तो जरूरी नहीं है कि वे मुंबई जा रहे हों. हो सकता है कि वे चेन्नई लैंड करें. तभी 82 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा के बाद भी फिर से राज्यसभा जाने के उनके फैसले को समझने की जरुरत है. साथ ही यह भी समझने की जरुरत है कि उनके प्रति भाजपा के सद्भाव का क्या मतलब है?

भाजपा ने संख्या कम होने के बावजूद बिहार में राज्यसभा चुनाव में अतिरिक्त उम्मीदवार दिया. ओडिशा और हरियाणा में भी राज्यसभा का अतिरिक्त उम्मीदवार उतारा. महाराष्ट्र में भी भाजपा की ओर से कहा गया था कि वह सातवां उम्मीदवार देगी. लेकिन उसने नहीं दिया और शरद पवार को निर्विरोध निर्वाचित होने दिया. बाद में संजय राउत की किताब की कहानियां आईं, जिसके मुताबिक शरद पवार ने कानूनी मामलों में अमित शाह की मदद की थी. बहरहाल, एक तरफ शरद पवार के दिवंगत भतीजे सुनेत्रा पवार की राजनीति है, जो पूरी तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के हिसाब से चल रही है तो दूसरी ओर शरद पवार का विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा जाना है.

पुडुचेरी में फिर हारे तो कांग्रेस जिम्मेदार

पुडुचेरी. पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. इसमें कांग्रेस के लिए सबसे आदर्श स्थिति दक्षिणी राज्यों में है. चुनाव से पहले हो रहे सर्वेक्षणों में बताया जा रहा है कि कांग्रेस केरल में चुनाव जीत सकती है.

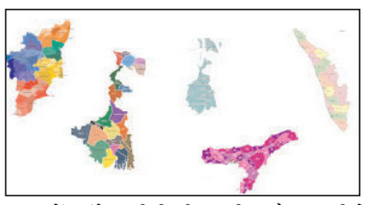

तमिलनाडु में भी डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन वापस सत्ता हासिल कर सकता है. लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मामला उलझा हुआ है. 30 विधानसभा सीटों वाले राज्य पुडुचेरी में 2016 में कांग्रेस जीती थी और दिल्ली में अहमद पटेल के बहुत करीबी रहे वी नारायणसामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था. लेकिन उन्होंने ऐसी सरकार चलाई कि 2021 के चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी और कांग्रेस के कारण डीएमके भी हारी. इस बार भी अगर पुडुचेरी में एनडीए चुनाव जीतता है तो उसका कारण कांग्रेस पार्टी होगी. कांग्रेस के खिलाफ पुडुचेरी में साफ साफ विरोध दिख रहा है. इसके बावजूद जैसे पिछली बार कांग्रेस ने जिद करके ज्यादा सीटें लीं और गठबंधन को हराया उसी तरह इस बार भी वह ज्यादा सीटें लेकर लड़ रही है. जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर उसने तमिलनाडु की तरह डीएमके को गठबंधन का नेतृत्व करने दिया होता तो हो सकता है कि जीत हो जाती.

गौरतलब है कि 2021 में कांग्रेस 14 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ दो सीट जीत पाई. दूसरी ओर डीएमके 13 सीटों पर लड़ कर छह पर जीती. इससे पहले 2016 में कांग्रेस ने 17 सीटें थीं. नारायणसामी ने कांग्रेस को 17 से दो सीट पर ला दिया. इस बार भी कांग्रेस ने जिद करके 16 सीटें ली हैं और डीएमके को पहले की तरह 13 सीटें दी हैं. हालांकि बाद में कांग्रेस ने पांच और सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जिनकी वजह से कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो गया है.

विशेष | दिल्ली में मालिवाल ने डुबाई थी केजरीवाल की लुटिया

अब पंजाब में राघव बिगाड़ेंगे मान का खेल!

चंडीगढ़. अरविंद केजरीवाल के करीबी रणनीतिकार माने जाने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की पार्टी से दूरी अचानक नहीं बनी, बल्कि इसकी शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ही हो गई थी.

पार्टी की गतिविधियों और प्रदर्शनों से उनकी लगातार गैरमौजूदगी ने संकेत दे दिया था कि उन पर भरोसा कम हो रहा है. इस पर मुहर तब लगी जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी राघव चड्ढा लंबे समय तक विदेश में रहे. दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं को फरवरी में राहत मिलने के बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. जंतर-मंतर पर आयोजित पार्टी की रैली से भी वे दूर रहे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, राघव चड्ढा काफी समय से सक्रिय राजनीति में कम दिखाई दे रहे थे और पार्टी लाइन से अलग रुख अपना रहे थे. उनके बीजेपी के करीब होने की अटकलों ने भी नेतृत्व को असहज किया. संसद में भी वे पार्टी के मुख्य एजेंडे के बजाय अन्य मुद्दे उठाते रहे, जिससे मतभेद और बढ़ गए. अंततः नेतृत्व ने उन्हें उपनेता पद से हटाने का फैसला किया. लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तब भी राघव विदेश में थे. पार्टी लाइन से अलग बयान, संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी और नेतृत्व से बिना चर्चा के संसद में मुद्दे उठाने जैसी बातों ने दूरी को और गहरा कर दिया.

पंजाब चुनाव पर असर?

जिस तरह स्वाती मालिवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, उसी तरह यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राघव चड्ढा भी अलग रुख अपना सकते हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी की ओर से उन्हें समर्थन मिल रहा है. अब देखने वाली बात यह होगी कि राघव चड्ढा आगे क्या रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में आम आदमी पार्टी और उनके बीच टकराव खुलकर सामने आता दिख रहा है.